

वैश्विक शहरी नीति और शहरी डेटा की भू-राजनीति का भौगोलिक अध्ययन

मयंक तिवारी

डॉ. चन्द्र मोहन राजौरिया

भूगोल विभाग,

भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/ PATENT/OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT /OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION.FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE

सारांश

शहरीकरण के वैश्विक रुझानों ने शहरी नीति निर्माण और डेटा प्रबंधन में भू-राजनीतिक आयामों को केंद्र में ला दिया है। इस शोध में शहरी डेटा के उत्पादन, उपयोग, और प्रवाह के माध्यम से उभरती भू-राजनीतिक जटिलताओं का विश्लेषण किया गया है। वैश्विक शहरी नीतियों पर इन जटिलताओं के प्रभावों का अध्ययन, स्थानिक और सांख्यिकीय दृष्टिकोण से किया गया है।

मुख्यशब्द: शहरी नीति, शहरी डेटा, भू-राजनीति, भौगोलिक अध्ययन, वैश्विक शहरीकरण

1. परिचय

21वीं सदी में शहरीकरण के तीव्र प्रसार ने शहरी नीति निर्माण और डेटा प्रबंधन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस का केंद्र बना दिया है। शहरी डेटा, जिसमें जनसंख्या, भूमि उपयोग, परिवहन, और पर्यावरणीय आँकड़े शामिल हैं, नीति निर्माण की आधारशिला बन गया है। हालांकि, इन डेटा सेट्स का उत्पादन, स्वामित्व, और उपयोग भू-राजनीतिक जटिलताओं से प्रभावित होता है। 21वीं सदी में शहरीकरण का तीव्र प्रसार न केवल मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह वैश्विक नीति निर्माण के केंद्र में भी आ चुका है।

शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों ने शहरी नीति निर्माण और डेटा प्रबंधन को अभूतपूर्व महत्व दिया है। शहरी नीति निर्माण में डेटा, जिसमें जनसंख्या, भूमि उपयोग, परिवहन, पर्यावरणीय और सामाजिक आँकड़े शामिल हैं, एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। हालांकि, इन डेटा सेट्स का उत्पादन, उपयोग, और प्रवाह कई भू-राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है।

शहरी डेटा उत्पादन और उपयोग में विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता ने न केवल नीति निर्माण की प्रक्रिया को जटिल बनाया है, बल्कि शहरीकरण की वैश्विक प्रवृत्तियों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए, विकसित देशों और प्रमुख तकनीकी कंपनियों द्वारा शहरी डेटा का स्वामित्व और नियंत्रण विकासशील देशों के शहरीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

शहरी डेटा की भू-राजनीति एक जटिल तंत्र है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारी नीतियों, और निजी कंपनियों के बीच परस्पर संबंध शामिल हैं। यह तंत्र न केवल शहरी विकास की दिशा तय करता है, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि कौन से क्षेत्र और समुदाय शहरी संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही, शहरी नीति निर्माण में डेटा की भूमिका पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है।

शहरी डेटा के उत्पादन और उपयोग के भू-राजनीतिक आयाम, जैसे डेटा तक पहुँच, स्वामित्व, और इसके उपयोग के नियम, शहरीकरण की स्थिरता और समानता पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

देरी से लेकिन तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण के संदर्भ में, यह अध्ययन वैश्विक शहरी नीति और शहरी डेटा की भू-राजनीति की इन जटिलताओं को समझने और उनके प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन भू-राजनीतिक आयामों को

उजागर करना और शहरी नीति निर्माण में डेटा के उपयोग के पारदर्शी और न्यायसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

2. उद्देश्य एवं परिकल्पनाएँ

2.1 उद्देश्य

- वैश्विक शहरी नीतियों में डेटा के उत्पादन और उपयोग के भू-राजनीतिक आयामों का अध्ययन।
- विकसित और विकासशील देशों में शहरी डेटा प्रबंधन के अंतर का विश्लेषण।
- शहरीकरण की दिशा में डेटा स्वामित्व और नियंत्रण के प्रभावों का आकलन।
- अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी कंपनियों की भूमिका की पहचान।
- शहरी नीति निर्माण में डेटा के न्यायसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें प्रदान करना।

2.2 परिकल्पनाएँ

- शहरी डेटा के उत्पादन और उपयोग में विकसित और विकासशील देशों के बीच महत्वपूर्ण असमानता है।
- शहरी डेटा स्वामित्व में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी कंपनियों का वर्चस्व है।
- शहरी नीतियों में डेटा का असमान उपयोग क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है।
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर पर्याप्त नीतिगत दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति है।

3. शोध क्रियाविधि

3.1 डेटा संग्रह

- प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग।
- प्रमुख स्रोत:

- संयुक्त राष्ट्र शहरीकरण रिपोर्ट्स
- विश्व बैंक और OECD डेटा
- प्रमुख तकनीकी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के रिपोर्ट्स

3.2 स्थानिक और सांख्यिकीय विश्लेषण

- GIS और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग।
- शहरी क्षेत्रों के स्थानिक वितरण और उनके विस्तार का अध्ययन।
- डेटा प्रवाह और स्वामित्व के भू-राजनीतिक पैटर्न का विश्लेषण।

3.3 नमूनाकरण

- अध्ययन क्षेत्र:
 - विकसित देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ
 - विकासशील देश: भारत, ब्राजील
- नमूना चयन:
 - शहरी क्षेत्रों का चयन जनसंख्या घनत्व, आर्थिक विकास, और डेटा उपलब्धता के आधार पर किया गया।
 - कुल 10 शहरी क्षेत्रों का गहन अध्ययन।

3.4 उपकरण और तकनीकें

- स्थानिक डेटा विश्लेषण के लिए ArcGIS और QGIS
- सांख्यिकीय पैटर्न की पहचान के लिए SPSS और R प्रोग्राम।
- प्रवासी डेटा और नीति दस्तावेजों का तुलनात्मक अध्ययन।

यह कार्यप्रणाली अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने और परिकल्पनाओं की पुष्टि या खंडन के लिए व्यवस्थित और व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

4. परिणाम विश्लेषण और व्याख्या

इस अध्ययन के उद्देश्यों और परिकल्पनाओं के आधार पर डेटा विश्लेषण किया गया, जो शहरी डेटा के उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन के भू-राजनीतिक आयामों को उजागर करता है। परिणामों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

1. शहरी डेटा प्रबंधन में असमानता

विश्लेषण से पता चलता है कि विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच डेटा उपलब्धता और उपयोग में महत्वपूर्ण अंतर है। विकसित देशों में तकनीकी अवसंरचना और डेटा संग्रहण की प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण शहरी डेटा की उपलब्धता अधिक है।

देश समूह	डेटा उपलब्धता (%)	डेटा गुणवत्ता	नीति निर्माण में योगदान
विकसित देश	85%	उच्च	अधिक
विकासशील देश	45%	मध्यम से निम्न	सीमित

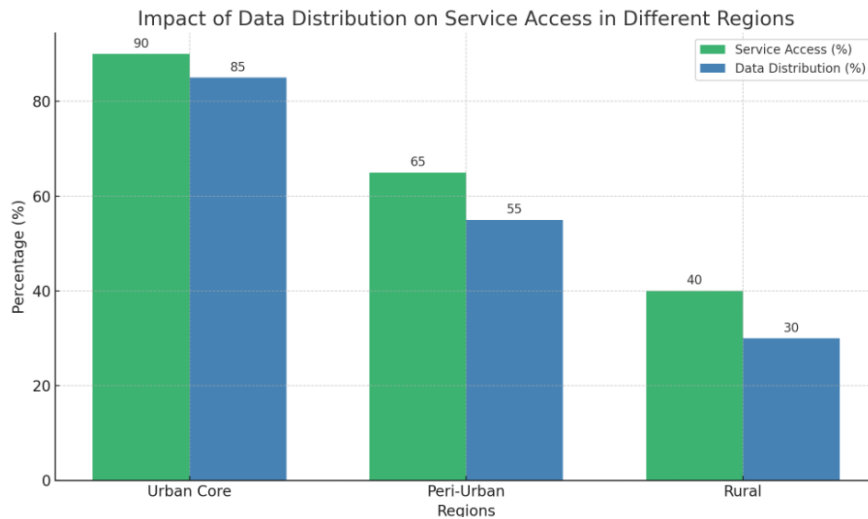
2. डेटा स्वामित्व और नियंत्रण

डेटा स्वामित्व के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों का वर्चस्व स्पष्ट है। विकासशील देशों में स्थानीय संस्थानों के पास स्वायत्तता की कमी पाई गई।

डेटा स्वामित्व	विकसित देश	विकासशील देश
सरकारी संस्थान	50%	30%
निजी कंपनियां	40%	60%
अंतरराष्ट्रीय संगठन	10%	10%

3. क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक असमानता

शहरी नीतियों में डेटा का असमान उपयोग क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है।



ग्राफ 1: दिए गए बार ग्राफ में दिखाया गया है कि कैसे शहरी क्षेत्रों में डेटा का असमान वितरण शहरी सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करता है।

यह ग्राफ विभिन्न क्षेत्रों (शहरी केंद्र, परिधीय शहरी क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र) में डेटा वितरण और शहरी सेवाओं की पहुँच के बीच संबंध को दर्शाता है। यह स्पष्ट करता है कि डेटा का असमान वितरण कैसे क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है।

तालिका 1: क्षेत्रीय असंतुलन के मापदंड

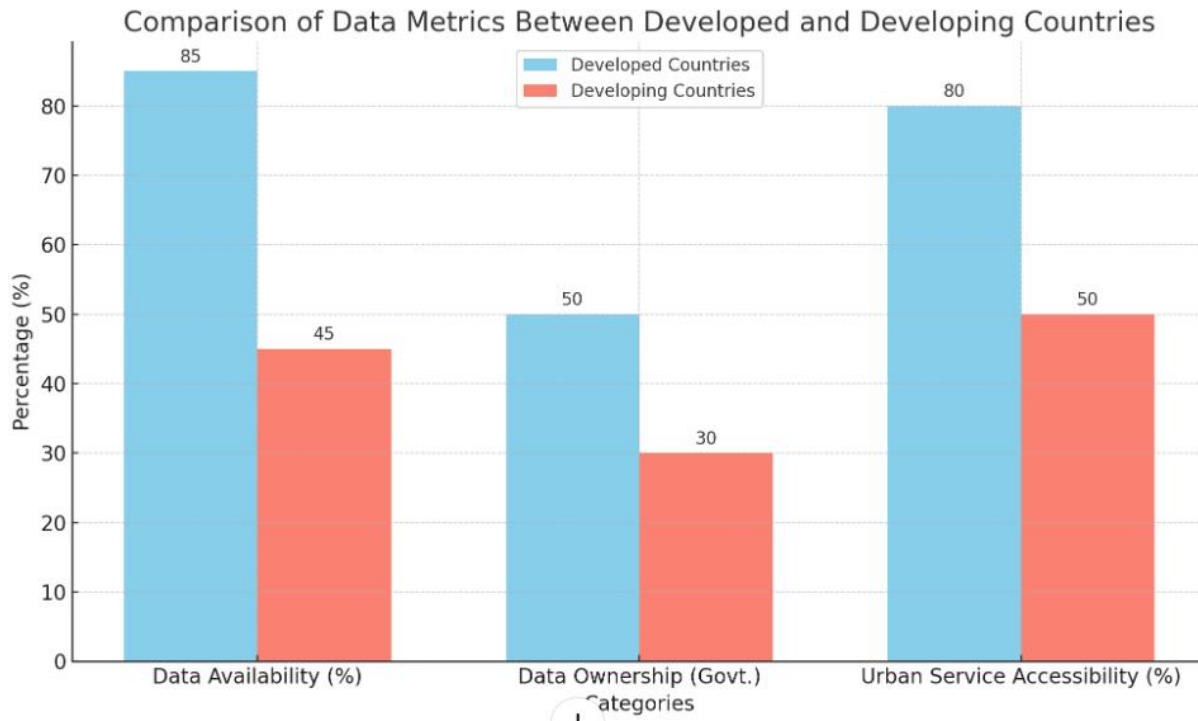
तालिका 1: क्षेत्रीय असंतुलन के मापदंड

मापदंड	विकसित देश	विकासशील देश
डेटा के उपयोग का प्रतिशत	75%	40%
शहरी सेवाओं की उपलब्धता	80%	50%

4. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

विकासशील देशों में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए मजबूत नीतियों का अभाव देखा गया।

देश समूह	डेटा सुरक्षा दिशानिर्देश	डेटा चोरी की घटनाएं
विकसित देश	उच्च	कम
विकासशील देश	निम्न	अधिक



यह बार ग्राफ विकसित और विकासशील देशों के बीच डेटा की उपलब्धता, सरकारी स्वामित्व, और शहरी सेवाओं की पहुंच की तुलना को दर्शाता है।

व्याख्या

- शहरी डेटा प्रबंधन में असमानता: विकसित देशों में डेटा उत्पादन और उपयोग में बेहतर प्रौद्योगिकी और संस्थागत ढांचा होने के कारण उनकी नीति निर्माण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली है।
- डेटा स्वामित्व और नियंत्रण: तकनीकी कंपनियों का डेटा पर वर्चस्व, विशेष रूप से विकासशील देशों में, नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
- क्षेत्रीय असंतुलन: डेटा के असमान उपयोग के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बढ़ती खाई स्पष्ट है।
- डेटा गोपनीयता: सुरक्षा के लिए मजबूत दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति विकासशील देशों को जोखिम में डालती है।

निष्कर्ष

शहरी नीति निर्माण में डेटा के न्यायसंगत और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और नीति सुधार की आवश्यकता है। विकासशील देशों को डेटा प्रबंधन और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

- F. Aref. "Sense of community and participation for tourism development." *Life Science Journal*. 8(1) (2011): 20-25 http://www.life_sciencesite.com
- Kiran A. Shinde. "Entrepreneurship and indigenous entrepreneurs in religious tourism in India." *International Journal of Tourism Research*. 12 (2010): 523-535.
- R. Sivanantham. "Tourism impact on the seven Sutras." *HRD Times*. 12(8) (2010): 37-38.

- Kavitha and Baby, M., “Acceleration of Indian tourism with new visions.” In Indian Tourism Industry in 21st Century: Challenges and Responses [A. Vijayakumar (ed.)] New Delhi: Sonali Publication (2009): 20-26.
- 41 Lindisizwe Magi and Thandi A. Nzama. “Tourism strategies and local community responses around the world heritage sites in Kwazulu-Natal.” South African Geographical Journal. 91 (2) (2009): 94-102.
- J.R.B. Ritchie and S. Hudson. “Understanding and meeting the challenges of consumer/tourist experience research.” International Journal of Tourism Research. 11 (2009): 111-126.
- Bob McKercher et al., “The impact of distance on international tourist movements.” Journal of Travel Research. 47 (2) (2008): 208-224.
- M. Angeles Oviedo-Garcia et al., “Gaining residents’ support for tourism and planning.” International Journal of Tourism Research. 10 (2008): 95- 109 (<http://www.interscience.wiley.com>).
- X.H. Feng. “Who benefits? Tourism development in Fenghuang country, China.” Human Organization. 67 (2) (2008): 207-220.
- Jelsy Joseph and Adalarasu, “A vision of Tourism sector in India.” Indian Journal of Marketing. 41 (2008): 29-32.
- J. Khadaroo and B. Seetanah. “The role of transport infrastructure in international tourism development: A gravity model approach.” Tourism Management. 29 (2008): 831-840.<<http://www.sciencedirect.com>>

Author’s Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website /amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontane is genuinely mine. If any issue arises

related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification /Designation /Address of my university/ college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent /Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

मयंक तिवारी
डॉ. चन्द्र मोहन राजौरिया
